

बाल श्रम उन्मूलन अभियान

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक **बाल श्रम** को समाप्त करने के लिये एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

अभियान के बारे में:

- इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना और पुनर्वास का समर्थन करना है ताकि प्रत्येक बच्चे को विकास और सीखने के उचित अवसर मिल सकें।
- सरकार जन सहभागिता बढ़ाने के लिये **वर्ल्ड बाल श्रम नषिध दविस** के अवसर पर **12 जून 2025** को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।

बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन और बाल पुनर्वास में उत्तर प्रदेश के प्रयास

- सरकार ने **बंधुआ मज़दूरी** के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच 1,408 व्यक्तियों का पुनर्वास किया है।
 - इन व्यक्तियों को 18.17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली है।
- वर्ष 2017-18 से 2024-25 के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने **12,426 बच्चों का पुनर्वास किया है**, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिली है।
- राज्य ने **1,089 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है**, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आय के लिये बाल श्रम पर निर्भर न रहें।
- **बाल श्रमिक वदिया योजना** के अंतर्गत सरकार ने 2,000 कामकाजी बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है।
 - उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मि, संरक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से **बाल श्रम से निपटने** के लिये वर्ष **2020 में इस राज्य-स्तरीय पहल की शुरुआत की**।
 - इस योजना का उद्देश्य **बाल श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में पुनः शामिल करना है**, ताकि उनके सीखने के अधिकार और सम्मानजनक भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ल्ड बाल श्रम नषिध दविस

- **परिचय:**
 - **वर्ल्ड बाल श्रम नषिध दविस** प्रतिवर्ष **12 जून** को मनाया जाता है।
 - इस दविस का उद्देश्य बाल श्रम की व्यापकता तथा इसे समाप्त करने के लिये आवश्यक तत्काल कार्रवाई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है।
- **वैश्विक सहयोग:**
 - यह दिन दुनिया भर की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज समूहों और नागरिकों को एकजुट करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
 - यह **बाल श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने** तथा उनके शोषण को समाप्त करने के व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने पर केंद्रित है।
- **बाल श्रम उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्य रूपरेखा:**
 - **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8.7** के अंतर्गत बाल श्रम का उन्मूलन एक प्रमुख उद्देश्य है।
 - SDG लक्ष्य 8.7 में नमिन्लखित के लिये तत्काल एवं प्रभावी उपाय करने का आह्वान करता है ताकि:
 - **जबरन मज़दूरी (Forced Labour)** का उन्मूलन किया जा सके,
 - **आधुनिक गुलामी और मानव तस्करी** को समाप्त किया जा सके,
 - **बाल श्रम के सबसे खराब रूपों**, जिसमें **बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग** भी शामिल है, को प्रतिबंधित और समाप्त किया

बंधुआ मज़दूरी

- भारत के [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#) द्वारा परिभाषित बंधुआ मज़दूरी, गुलामी का एक रूप है **जिसमें ऋण बंधन कहा जाता है** जो सदियों से जारी है ।
- इसे आधुनिक गुलामी का सबसे गंभीर रूप माना जाता है, जहाँ श्रमिकों को कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिये मज़बूर किया जाता है । इसमें किसी नियोक्ता द्वारा ऋण चुकाने के लिये एक नश्चिन्ता अवधि के लिये बना वेतन के काम करने के लिये मज़बूर किया जाना शामिल हो सकता है ।

बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 23: यह [मानव तस्करी](#) और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, शोषण तथा अपमानजनक कार्य स्थितियों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।
- अनुच्छेद 24: यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी खतरनाक कार्य करने के लिये नियोजित नहीं किया जा सकता ।
- अनुच्छेद 39: इसमें उन संधिधर्तों की रूपरेखा दी गई है जिनका राज्य को पालन करना चाहिये, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिये आजीविका के समान अधिकार, [समान कार्य के लिये समान वेतन](#), श्रमिकों के स्वास्थ्य और **बच्चों की भलाई की सुरक्षा तथा बच्चों को स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से विकसित होने के अवसर सुनिश्चित करना** शामिल है ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/child-labour-eradication-campaign>

